

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

**निगरानी संख्या-124/2016/नागौर**

सीताराम शर्मा पुत्र स्व. श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा,  
जाति-ब्राह्मण, निवासी-अशोक विहार,  
आनासागर सरक्यूलर रोड़ अजमेर

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये  
उप-पंजीयक, भैरून्दा, तह-रीयांबड़ी(नागौर)

...अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम-सदस्य

**उपस्थित :**

श्री जे.पी.शर्मा,  
अभिभाषक  
श्री आर. के. अजमेरा  
उप-राजकीय अभिभाषक

....प्रार्थी की ओर से

....अप्रार्थी-राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.06.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त अजमेर (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 14.10.2014 प्रकरण संख्या 337/2014 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप-पंजीयक, भैरून्दा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री वासुदेव मित्तल पुत्र स्व० श्री गौरी शंकर मित्तल निवासी ब्रह्मपुरी अजमेर (विक्रेता) ने अपने स्वामित्व की कृषि भूमि खाता नं० 70 (पुराना) 170(नया) खसरा नं० 230/103 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी-2, वाकै ग्राम किला, उप तहसील भैरून्दा, तहसील डेगाना जिला नागौर को प्रार्थी व तीन अन्य क्रेता को रू० 4,25,000/- में विक्रय कर, विक्रय दस्तावेज उप पंजीयक, भैरून्दा के समक्ष दिनांक 20.12.2011 को पेश किया। उप पंजीयक ने दस्तावेज को पंजीबद्ध कर संबंधित प्रार्थी को लौटा दिया परन्तु आंतरिक लेखा जांच/महालेखाकर जांच दल द्वारा मौका निरीक्षण के पश्चात प्रश्नगत दस्तावेज की कुल मालियत रू० 25,41,000/- मानी जाकर, धारा 54 के अन्तर्गत रेफरेन्स तैयार कर कलक्टर(मुद्रांक) को पेश किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर, क्रेता सीताराम व विक्रेता को नोटिस जारी किये। रेफरेन्सानुसार राशि जमा नहीं कराने पर, कलक्टर (मुद्रांक) ने प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार करते हुए, प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत उपरोक्तानुसार आंकी जाकर, कमी मुद्रांक रू० 1,18,844/-, कमी पंजीयन शुल्क रू० 21,160/-, शास्ति रू० 92,410/- एवं ब्याज रू० 59,330/- कुल रू० 2,91,744/- प्रार्थी क्रेता से वसूल करने का आदेश पारित किया। कलक्टर(मुद्रांक) के इस आदेश से व्यथित होकर, प्रार्थी-क्रेता द्वारा यह निगरानी पेश की गयी है।

२३

लगातार.....2

3. निगरानी दर्ज की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।
4. बहस विद्वान अभिभाषकगण की उभयपक्ष सुनी गई।
5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। निर्णय की जानकारी नीलामी कार्यवाही से हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 की पालना किये बिना व बिना कोई जांच किए रेफरेन्स स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स खारिज किया जावे।
6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने तथा प्रार्थीया द्वारा धारा 5 में अंकित कारण की निर्णय की जानकारी नीलामी कार्यवाही के आधार पर हुई संतोषजनक होने के दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।
9. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर के निगरानीधीन आदेश के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरुद्ध निगरानी होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति देते। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of

2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किये गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :-

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case is discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretion by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally ceases. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent. Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appear to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

10. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेंस आंतरिक लेखा जांच दल के इस आक्षेप पर आधारित था कि दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 4 के अनुसार भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 89 से ग्राम किला को जाने वाली डामर रोड़ पर स्थित है जिस पर डी.एल.सी. के पृष्ठ सं. एस.नं. 54 के अनुसार 2,54,100/- प्रति बीघा की दर लगनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस के इस तथ्य के सम्बन्ध में न तो कोई जांच की है व न ही अपने निर्णय में इसे स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई विवेचन या विश्लेषण किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

11. रेकार्ड के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति जो विक्रेता द्वारा विक्रय की गई थी उसमें प्रार्थी के अलावा अन्य तीन क्रेता श्री रमेश चन्द पुत्र श्री पदम चन्द जैन, वैशाली नगर अजमेर, श्री सुनील पुत्र श्री प्रभुदयाल गोयल केसर गंज अजमेर तथा जिनेश पुत्र श्री मूल चन्द बोहरा वैशाली नगर अजमेर भी थे लेकिन उप पंजीयक/आंतरिक लेखा जांच दल ने इसी सम्पत्ति के चार क्रेता होने के बावजूद अन्य को पक्षकार नहीं बनाकर केवल प्रार्थी के विरुद्ध ही खरीद सम्पत्ति मानी जाकर वसूली का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अतः उन्हें भी पक्षकार बनाया जावे।

12. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

27

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना-विश्लेषण सहित निर्णय पारित नहीं करने के कारण विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही शेष क्रेतागण (पैरा संख्या 11) को पक्षकार बनाकर उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.08.2017 को पेश हों।

14. निर्णय सुनाया गया।

( नैथूराम )  
सदस्य